लचीलापन और स्थिरता ट्रस्ट (आरएसटी)

सन्दर्भ

भारतीय स्टेट बैंक ने निर्यातकों से कहा है कि वे बांग्लादेश के साथ डॉलर और अन्य प्रमुख मुद्राओं में सौदे करने से बचें क्योंकि यह बांग्लादेश के गिरते विनिमय भंडार के जोखिम को कम कर सकता है।

प्रमुख बिंदु

• बांग्लादेश की 416 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण ऊर्जा और भोजन की बढ़ती कीमतों से जूझ रही है।

• इसके परिणामस्वरूप चालू खाता घाटा बढ़ता जा रहा है और विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा है जिसने आईएमएफ जैसे वैश्विक उधारदाताओं की ओर रुख करने के लिए मजबूर किया है।

• बांग्लादेश आईएमएफ से 4.5 अरब डॉलर का ऋण मांग रहा है, जो आईएमएफ रेजिलिएंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट के तहत अपनी अधिकतम 1 अरब डॉलर की पात्रता से अधिक है।

आईएमएफ के आरएसटी के बारे में

• उद्देश्य : दीर्घकालिक संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान करना जो भुगतान संतुलन के लिए महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक जोखिमों को शामिल करती हैं।
जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन और स्थिरता का निर्माण करना और महामारी की तैयारियों का समर्थन करना।

• पात्रता: कमजोर निम्न और मध्यम आय वाले सदस्य और छोटे राज्य: आईएमएफ की सदस्यता का लगभग तीन-चौथाई।

• एक्सेस : किसी सदस्य के आईएमएफ कोटे का 150% या एसडीआर 1 बिलियन, जो भी कम हो कोई सदस्य देश प्राप्त कर सकता है ।

उधार देने की शर्तें:

कम ब्याज दरें (तीन महीने की एसडीआर ब्याज दर पर मामूली मार्जिन) लंबी अवधि (20 साल और 10 साल की छूट अवधि) की परिपक्वता के साथ।
कम आय वाले सदस्यों को अधिक रियायती शर्तों से लाभ होने के साथ, टियरेड ब्याज संरचना देश के समूहों में वित्तपोषण की शर्तों को अलग करती है।

• संरचना: एक ऋण-आधारित ट्रस्ट (पीआरजीटी के समान) जिसके संसाधन मजबूत स्थिति वाले आईएमएफ सदस्यों के स्वैच्छिक योगदान के आधार पर जुटाए जाते हैं।

आरएसटी की आवश्यकता क्यों है?

• आईएमएफ के मौजूदा ऋण देने वाले टूलकिट के पूरक के लिए जो दो प्रमुख सुविधाओं के माध्यम से लघु और मध्यम अवधि की चुनौतियों का जवाब देता है:
सामान्य संसाधन खाता (जीआरए) जो सभी देशों के लिए सुलभ है।
गरीबी में कमी और विकास ट्रस्ट (पीआरजीटी): कम आय वाले देशों के लिए रियायती शर्तों (वर्तमान में शून्य ब्याज दर) पर उपलब्ध है।

अनुसूचित जाति का दर्जा और धार्मिक अल्पसंख्यक

सन्दर्भ

केंद्र अनुसूचित जाति (एससी) के सदस्यों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन कर रहा है, जो हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के अलावा अन्य धर्मों में परिवर्तित हो गए हैं।

कानूनी प्रावधान

• संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत, राष्ट्रपति जातियों, नस्लों या जनजातियों के कुछ हिस्सों या समूहों को निर्दिष्ट कर सकते हैं जिन्हें अनुसूचित जाति माना जाएगा।

• उपरोक्त अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 यह निर्धारित करता है कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से अलग धर्म को मानने वाले किसी भी व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता है।

• मूल आदेश में केवल हिंदुओं को शामिल किया गया था और 1956 में सिखों को शामिल करने के लिए और 1990 में बौद्धों को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया था।

एसटी, ओबीसी और धार्मिक अल्पसंख्यक

• मुद्दा एससी तक ही सीमित है क्योंकि एसटी और ओबीसी के लिए कोई धर्म-विशिष्ट जनादेश नहीं है।

• डीओपीटी के अनुसार, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के अधिकार उसके धार्मिक विश्वास से स्वतंत्र हैं। मंडल आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के बाद, कई ईसाई और मुस्लिम समुदायों को ओबीसी की केंद्र या राज्यों की सूची में जगह मिली है।

रंगनाथ मिश्र आयोग

• अक्टूबर 2004 में, केंद्र ने धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के बीच सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण के उपायों की सिफारिश करने के लिए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है।

• आयोग ने सिफारिश की कि अनुसूचित जाति का दर्जा पूरी तरह से धर्म से अलग कर दिया जाए और एसटी की तरह धर्म-तटस्थ बनाया जाए, लेकिन तत्कालीन सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था।

सच्चर समिति की रिपोर्ट

• मार्च 2005 में, मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था।

• समिति ने पाया कि धर्मांतरण के बाद दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अध्ययन

• 2007 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा और समाजशास्त्री सतीश देशपांडे के नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि दलित ईसाइयों और दलित मुसलमानों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता है।

कलर क्रांति

सन्दर्भ

चीन ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्यों से अपील की कि वे एक-दूसरे का सहयोग करें ताकि विदेशी शक्तियों को "कलर क्रांतियों" को उकसाकर देशों को अस्थिर करने से रोका जा सके।

कलर क्रांति क्या हैं

• कलर क्रांतियां उन विद्रोहों की एक श्रृंखला को संदर्भित करती हैं जो पहली बार 2000 के दशक की शुरुआत में पूर्वी यूरोप के पूर्व साम्यवादी देशों में शुरू हुई थीं।

• हालांकि, उनका उपयोग मध्य पूर्व और एशिया में लोकप्रिय आंदोलनों के संदर्भ में किया जाता है।

• प्रदर्शनकारी अक्सर एक विशिष्ट रंग पहनते हैं, जैसे कि यूक्रेन की नारंगी क्रांति में, लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल ट्यूनीशिया में चमेली क्रांति जैसे फूलों के नाम पर आंदोलनों का वर्णन करने के लिए भी किया गया है।

क्रांति के लक्षण

• सड़कों पर बड़े पैमाने पर लामबंदी।

• स्वतंत्र चुनाव या शासन परिवर्तन की मांग।

• सत्तावादी नेताओं को हटाने का आह्वान।

लोकप्रिय क्रांतियों की सूची

• नारंगी क्रांति (यूक्रेन, 2004-05): चुनावी धांधली की अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों की प्रतिक्रिया में विरोध के कारण फिर से चुनाव हुए जिसमें पहले हारे हुए उम्मीदवार विजयी हुए।

• ट्यूलिप क्रांति (किर्गिस्तान, 2005): इसे पहली किर्गिज़ क्रांति भी कहा जाता है, इस आंदोलन के कारण तत्कालीन किर्गिस्तान के राष्ट्रपति को हटा दिया गया था। चुनाव में धांधली की अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों की प्रतिक्रिया में विरोध भड़क गया था।

• चमेली क्रांति (ट्यूनीशिया, 2010-11): देश में अंतर्निहित भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और राजनीतिक स्वतंत्रता की कमी के जवाब में।

• लोटस रेवोल्यूशन (मिस्र, 2011): पुलिस की बढ़ती बर्बरता के जवाब में।

विश्व बैंक ने पंजाब को 15 करोड़ का कर्ज मंजूर किया

सन्दर्भ

विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने हाल ही में राज्य को अपने वित्तीय संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करने और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने में मदद करने के लिए पंजाब को $150 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

• ऋण की परिपक्वता अवधि 15 वर्ष है।

• पंजाब का विकास क्षमता से कम रहा है।

• विश्व बैंक की सहायता से शुरू की जाने वाली नई परियोजनाओं से पंजाब को अपने विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

• राज्य अपनी योजना, बजट और निगरानी कार्यों को बढ़ाने में सक्षम होगा। डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल में भी इजाफा होगा।

• राज्य के लोग कानूनी और नीतिगत ढांचे में नए सुधारों को भी देखेंगे।
• यह नई परियोजना राज्य की नई डेटा नीति के कार्यान्वयन का समर्थन करेगी, जिसका उद्देश्य विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पहलों को एक साथ लाना और आवश्यक सेवाओं को वितरित करते समय संभावित रिसाव को कम करना है।
• परियोजना के तहत नगर निगमों को सेवा वितरण में सुधार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रणाली शुरू करने की पहल की जाएगी।

विश्व बैंक

• विश्व बैंक एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो पूंजी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सरकारों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है।
• विश्व बैंक पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (आईबीआरडी) और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) का सामूहिक नाम है, जो विश्व बैंक समूह के स्वामित्व वाले पांच अंतरराष्ट्रीय संगठनों में से दो हैं।
• इसकी स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ की गई थी।

IBRD International Bank for Reconstruction & Development	IDA International Development Association	IFC International Finance Corporation	MIGA Multilateral Investment and Guarantee Agency	ICSID International Center for Settlement of Investment Disputes
Est. 1945	Est. 1960	Est. 1956	Est. 1988	Est. 1966
Role:				
To promote institutional, legal and regulatory reform	To promote institutional, legal and regulatory reform	**To promote private sector development**	To provide instruments for political investment risk management	To provide facilities for conciliation and arbitration of international investment disputes.
Clients:				
Governments of member countries with per capita income between $1,025 and $6,055.	Governments of poorest countries with per capita income of less than $1,025	**Private companies in 183 member countries**	Foreign investors in member countries	Foreign investors in member countries
Products:				
- Technical assistance - Loans - Policy Advice	- Technical assistance - Interest Free Loans - Policy Advice	**- Equity/Quasi-Equity - Long-term Loans - Risk Management - Advisory Services**	- Political Risk Insurance	- Dispute settlement facilities

यूएई पहला लूनर रोवर लॉन्च करेगा

सन्दर्भ

संयुक्त अरब अमीरात नवंबर 2022 में अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च करेगा।

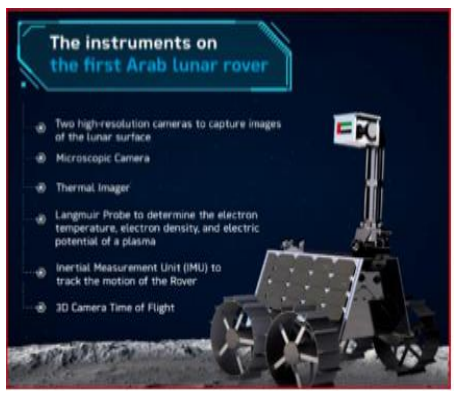

प्रमुख बिंदु

• दुबई के शासक परिवार के लिए नामित राशिद रोवर को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। चंद्र मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।
• यदि चंद्रमा मिशन सफल होता है, तो संयुक्त अरब अमीरात और जापान केवल अमेरिका, रूस और चीन के रैंक में शामिल होंगे, जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर एक अंतरिक्ष यान उतारा है।
• पहले से ही, एक अमीराती उपग्रह लाल ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए मंगल की परिक्रमा कर रहा है।
• राशिद रोवर से चंद्रमा की सतह, चंद्रमा की सतह पर गतिशीलता और विभिन्न सतहों के चंद्र कणों के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इसका अध्ययन करने की उम्मीद है।
• 10-किलोग्राम (22-पाउंड) रोवर में दो उच्च-रिज़ॉल्यूशन कैमरे, एक सूक्ष्म कैमरा, एक थर्मल इमेजरी कैमरा, एक जांच और अन्य उपकरण होंगे।

'प्रोजेक्ट पुथरी'

सन्दर्भ

डैनफॉस इंडिया ने सरकारी स्कूल की छात्राओं का मार्गदर्शन करने के लिए 'प्रोजेक्ट पुथरी' के लिए अवतार ह्यूमन कैपिटल ट्रस्ट के साथ साझेदारी की है।

प्रमुख बिंदु

• इसे तमिलनाडु में सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए करियर सहायता कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया है।

कार्यक्रम का उद्देश्य है:
छात्राओं का चयन करना और उन्हें आवश्यक कौशल और रोजगार योग्यता के साथ विकसित करना,
उनके आत्मनिर्भर करियर के लिए प्रशिक्षण,
छात्राओं की शिक्षा और सशक्तिकरण।
• कार्यक्रम विद्वानों द्वारा विशेष कक्षाएं, कुशल सलाहकारों द्वारा करियर मार्गदर्शन और उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करके लड़कियों की सहायता करता है।

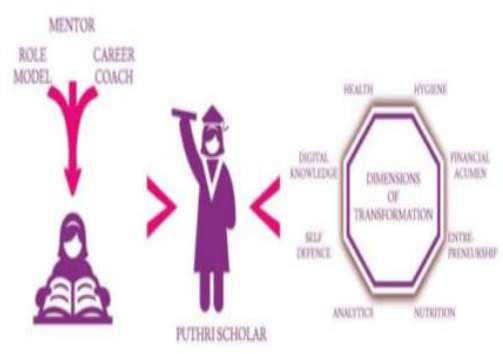

अनुवाद संपदा

सन्दर्भ
अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय ने अंग्रेजी से क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च शिक्षा सामग्री का अनुवाद शुरू किया है।

प्रमुख बिंदु
• भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा के लिए पठन सामग्री की आवश्यकता देश भर के छात्रों, शिक्षकों और संस्थानों द्वारा महसूस की गयी है।
• भारतीय भाषाओं में ऐसी पठन सामग्री की अनुपलब्धता जो छात्रों को उनकी अपनी भाषाओं में आधुनिक विचारों के साथ जुड़ने में मदद कर सकती है और जो उनके संदर्भों के लिए प्रासंगिक हैं, शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और समावेश सुनिश्चित करने में एक प्रमुख बाधा है।
• क्षेत्रीय भाषाओं में अवधारणाओं और सूक्ष्म बहसों की उपलब्धता विविध संदर्भों में विचारों के आदान-प्रदान और विकास को सक्षम बनाएगी।

उद्देश्य
• विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी और भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री हिंदी और कन्नड़ में सभी के लिए उपलब्ध और सुलभ बनाना।
• हिंदी और कन्नड़ में शैक्षणिक सामग्री के व्यापक प्रसार को सक्षम करना।
• विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के छात्रों, शिक्षाविदों और चिकित्सकों को हिंदी और कन्नड़ में शैक्षणिक सामग्री की खोज, उपयोग और पुन: उपयोग करने में सक्षम बनाना।
• फाउंडेशन के रिसोर्स पर्सन द्वारा किए गए शिक्षक-विकास प्रयासों के लिए प्रासंगिक सामग्री विकसित करना।
• हिंदी और कन्नड़ में मूल लेखन, पठन, विचार-विमर्श और संभाषण को बढ़ावा देना और इसके लिए एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना।

अन्य महत्त्वपूर्ण ख़बरें

अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम

सन्दर्भ
भारतीय वित्त मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) से आग्रह किया है कि वह भारत को अगले दो वर्षों में 2 अरब डॉलर से अधिक और अगले तीन-चार वर्षों में 3-3.5 अरब डॉलर तक उधार दे।

आईएफसी के बारे में
• डब्ल्यूबी समूह के सदस्य के रूप में 1956 में स्थापित, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। आमतौर पर डब्ल्यूबी की निजी क्षेत्र की निवेश शाखा के रूप में जाना जाता है। यह
एक निगम है जिसके शेयरधारक सदस्य सरकारें (भारत सहित) हैं जो प्रदत्त पूंजी प्रदान करते हैं और महत्वपूर्ण मामलों पर मतदान करने का अधिकार रखते हैं।
• संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा शेयरधारक है जिसके बाद यूके और चीन का स्थान है।
• यह देशों को अपने निजी क्षेत्रों को विभिन्न तरीकों से विकसित करने में मदद करता है:
(i) कंपनियों में निवेश।
(ii) पूंजी जुटाना।
(iii) निजी निवेश को प्रोत्साहित करने और निवेश के माहौल में सुधार के लिए व्यवसायों और सरकारों को सलाह देना।

एनर्जी एक्सेस एक्सप्लोरर (ईएई)

प्रमुख बिंदु
• इसे पहली बार 2021 में झारखंड राज्य में और हाल ही में असम में, 31 अगस्त, 2022 को पेश किया गया था।
• सभी भारतीय घरों में लगभग पूर्ण विद्युतीकरण के दावों के बावजूद, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ऊर्जा पहुंच में कई कमियां हैं। यह प्रणाली नीति निर्माताओं को ऊर्जा पहुंच अंतराल को पाटने और इसे बढ़ाने के लिए डेटा प्रदान करती है।

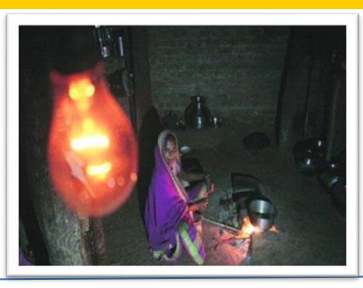

• सहज बिजली हर घर योजना के तहत - सौभाग्य योजना अक्टूबर 2017 में शुरू की गई, सरकार ने देश के सभी विद्युतीकृत घरों में अंतिम मील कनेक्टिविटी और बिजली कनेक्शन
पर ध्यान केंद्रित किया था। विद्युत मंत्रालय के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) लिमिटेड, योजना के संचालन के लिए नोडल एजेंसी है।

जीवाश्म ईंधन की वैश्विक रजिस्ट्री

सन्दर्भ

दुनिया के जीवाश्म ईंधन उत्पादन, भंडार और उत्सर्जन पर नज़र रखने के लिए हाल ही में लॉन्च किया गया अपनी तरह का पहला डेटाबेस।

प्रमुख बिंदु

• सूची में 89 देशों में 50,000 से अधिक तेल, गैस और कोयला क्षेत्रों के डेटा शामिल हैं, जो वैश्विक उत्पादन के 75 प्रतिशत को कवर करते हैं।

• शीर्ष 12 सबसे अधिक प्रदूषण करने वाले स्थल सभी खाड़ी या रूस में थे। यह दर्शाता है कि ये भंडार 3.5 ट्रिलियन टन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन उत्पन्न करेंगे, जो कि औद्योगिक क्रांति के बाद से उत्पादित सभी उत्सर्जन से अधिक है।
• महत्व: जीवाश्म ईंधन उत्पादन के आसपास पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाकर, रजिस्ट्री का उद्देश्य शेष कार्बन बजट पर निष्कर्षण प्रभावों की समझ में सुधार करना और अंततः निर्णय निर्माताओं द्वारा इसके प्रबंधन को सूचित करना है।

भारत और मिस्र सहयोग

सन्दर्भ

भारत और मिस्र दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच समयबद्ध तरीके से सहयोग बढ़ाने के प्रस्तावों की पहचान करने पर सहमत हुए हैं।

प्रमुख बिंदु

• दोनों पक्षों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के कदमों पर चर्चा की और संयुक्त अभ्यास के संचालन और विशेष रूप से उग्रवाद के क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए कर्मियों के आदान-प्रदान को बढ़ाने के लिए आम सहमति पर पहुंचे।
• दोनों मंत्रियों ने क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया और विश्व में शांति और स्थिरता के लिए भारत और मिस्र के योगदान को स्वीकार किया।
• उन्होंने आपसी हित के सभी क्षेत्रों में रक्षा सहयोग बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए रक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए।
• महत्व: समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत-मिस्र संबंधों में नई गति और तालमेल स्थापित करेगा।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUC GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 91 4 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com